साम्राज्यवादी वैश्वीकरण और भारत

यह सही है कि वैश्वीकरण के बाद अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों का सम्मिलित विकास दर बढ़ा है, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों की स्थिति पर गौर करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि खेती और उद्योग-धंधों का विस्तार करने और उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने के बजाये जल्दी से जल्दी और बेहिसाब मुनाफ़ा देने वाले क्षेत्रों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। नये उद्योगों में उच्च तकनीक अपनाये जाने और पूंजी केंद्रित होने के चलते रोजगार के नये अवसर पैदा होने की संभावना बहुत ही कम है। हमारे देश और देश की बहुसंख्यक जनता से इस विकास का कोई लेना-देना नहीं है।

1990-91 से 2007-08 के बीच सकल घरेलू उत्पाद में खेती का हिस्सा 32 फ़ीसदी से घट कर 17.8 फ़ीसदी रह गया और उद्योग का हिस्सा 27 फ़ीसदी से घट कर 19.4 फ़ीसदी रह गया। दूसरी ओर इसी बीच सेवा क्षेत्र का हिस्सा 41 फ़ीसदी से बढ़ कर 62.9 फ़ीसदी हो गया। सेवा क्षेत्र में भवन निर्माण, व्यापार, होटल, यातायात, संचार, वित्त, बीमा, स्थायी संपत्ति और व्यापारिक सेवायें आदि शामिल हैं। 2001 से 2008 के बीच खेती की विकास दर 2.8 प्रतिशत, उद्योग की 7.1 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र की 9 प्रतिशत थी। सेवा क्षेत्र में भी सबसे ऊंची विकास दर वित्त और वित्त से संबंधित क्षेत्रों में ही रही है।

ये आंकड़े वैश्वीकरण के दौर में देश की कुल पैदावार में विकास की दिशा और शासक वर्गों की प्राथमिकता का पूरी तरह पर्दाफाश कर देते हैं। भारत की 70 फ़ीसदी आबादी गांवों में रहती है जिसमें से अधिकांश लोग़ खेती पर निर्भर हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वैश्वीकरण के दौर में देश की कुल पैदावार में खेती का हिस्सा पहले की तुलना में लगभग आधा हो गया और उसकी विकास दर भी सेवा क्षेत्र की तुलना में एक तिहाई से भी कम है। उद्योग की स्थिति भी बदतर हुई है। अर्थव्यवस्था में उसकी भागीदारी भी इस दौरान काफी कम हुई है। खेती और उद्योग ही देश की बहुसंख्यक आबादी का भरण-पोषण करते हैं। उत्पादन की कीमत पर सेवा क्षेत्र का बेमेल और विषमतापूर्ण विकास इस बात का परिणाम है कि यह तथाकथित विकास साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी द्वारा पैदा किये गये सट्टेबाजी के बुलबुलों का नतीजा है। इसने ऊंचे वेतन और विलासितापूर्ण जीवन शैली वाला एक विशिष्ट वर्ग पैदा किया है जो दुनिया के वित्तीय दायरे से जुड़ा है, लेकिन देश की वास्तविक अर्थव्यवस्था से इसे कुछ भी लेना-देना नहीं है।

आम तौर पर लोग़ यही सोचते हैं कि जो लोग़ सट्टेबाजी में पैसा लगाते हैं, उनका ही पैसा डूबता है, हमें भला इससे क्या लेना-देना। लेकिन बात इतनी सरल नहीं है।

परजीवी सटोरिया पूंजी के वर्चस्व के इस दौर में सातजिक आय के बंटवारे को दुबारा नये सिरे से निर्धारित किया गया है। मध्य वर्ग के एक हिस्से को अपने पक्ष में मिलाने के लिए शासक वर्गों ने उनकी आय में बेतहाशा वृद्धि की है। पांचवें और छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू किये जाने के साथ ही उच्चतम और न्यूनतम वेतनमान में भारी अंतर पैदा करना इसका एक उदाहरण है। साथ ही आयकर में छूट, ब्याज दर में कटौती और शेयर बाज़ार से होने वाली आय पर छूट देकर नवधनाढ्यों को सट्टेबाजी के लिए ललचाया गया। दूसरी ओर, चूंकि मज़दूरों, किसानों और स्वरोज़गार में लगे लोग़ों की कीमत पर इस अल्पसंख्यक मध्य वर्ग को मालामाल किया गया, इसलिए मेहनतकश आम जनता की आय में लगातार गिरावट आई और उसकी कंगाली बढ़ती गई। जब उद्योग-धंधे नहीं बढ़ेंगे, लोग़ों को स्वाभिमान से जीने लायक रोज़गार नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि असंगठित क्षेत्र में गुलामी करने वाले तथा घरेलू नौकर के रूप में खटने, मालिश करने, खाना बनाने, टैक्सी चलाने, चौकीदारी करने और कूड़ा बटोरने वाले कौड़ियों के मोल बिकने को तैयार लोग़ नव धनपतियों की गुलामी के लिए आसानी से उपलब्ध होंगे। यह तो सट्टेबाज पूंजी के मालिकों और उनके रहनुमाओं द्वारा बनायी गई दुनिया की एक झलक मात्र है। पूरी तस्वीर कहीं ज़्यादा घृणास्पद, क्षोभकारी और आक्रोश से भर देने वाली है।

जिस विकास का इतना ढोल पीटा गया, उसका देश की अधिकांश जनता के लिए भला क्या मतलब है? 42 फ़ीसदी जनता (45.6 करोड़) सरकारी ग़रीबी रेखा से नीचे जीने को अभिशप्त है जबकि ग़रीबी रेखा का सरकारी पैमाना इतना नीचा है कि कई अर्थशास्त्री इसे 'कंगाली रेखा' कहते हैं। असंगठित क्षेत्र आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश की 77 फ़ीसदी आबादी (80 करोड़ लोग़) 20 रुपये प्रतिदिन पर गुज़ारा करते हैं। काम करने की आयु वाले 58 फ़ीसदी लोग़ बेरोज़गार हैं। इस विकास ने मुट्ठी भर लोग़ों के लिए स्वर्ग का निर्माण किया तो दूसरी ओर करोड़ों लोग़ों की पहले से ही बदहाल ज़िंदगी को साक्षात नरक में बदल दिया। जिस दौरान भारत में करोड़पतियों-अरबपतियों की संख्या मे इज़ाफ़े की गर्वीली खबरें मीडिया की सुर्ख़ियों में थी, उसी समय लाखों किसानों ने आत्महत्यायें कीं, करोड़ों बच्चे भूख और कुपोषण के शिकार हुए और करोड़ों लोग़ ऐसी बीमारियों से मर गये जिनका आसानी से इलाज संभव है। इस तरह बड़े पूंजीपतियों को बेतहाशा सब्सिडी दे कर अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर पहुंचाया गया तो दूसरी ओर ग़रीबों के मुंह से निवाला छीन कर उन्हें मौत की ओर धकेल दिया गया।

इन सच्चाइयों की रोशनी में विकास के गुब्बारे को देखा जाये तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि वैश्वीकरण विश्व पूंजीवादी संकट को भारत सहित तीसरी दुनिया की जनता पर थोपने के अलावा कुछ नहीं। अमेरिकी संकट ने 'आर्थिक सुधार' के पैरोकारों की विदेशी पूंजी और विदेशी बाज़ार पर निर्भरता की कलई भी खोल दी है, क्योंकि पहला झटका उन्हीं क्षेत्रों को लगा जो निर्यात कर के डॉलर कमाने में मशगूल थे।

-(देश-विदेश, पुस्तिका-एक से)

हरियाणा में डॉक्टरों का आंदोलन

फरीदाबाद (म.मो.) अपनी मांगे न माने जाने से खौफजदा राज्य भर के चिकित्सकों ने संघर्ष की घोषणा कर दी है। चिकित्सकों ने राज्य सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वे 7-8 जून को अवकाश पर रहेंगे। इसी दिन चिकित्सकों ने सामूहिक इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है। पर ऐसा नहीं हुआ। चिकित्सकों का यह आंदोलन वेतन विसंगति को लेकर है। चिकित्सकों ने इस समस्या को लेकर राज्य सरकार से बातचीत करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो पूरे प्रदेश में चिकित्सा सेवा ठप्प कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में करीब साढ़े 22 सौ चिकित्सक हैं। इनकी प्रमुख मांग है - एंट्री लेवल पर क्लॉस टू के समकक्ष वेतनमान देना, बंचिग का लाभ देना, एनपीए बेसिक पे का हिस्सा देना तथा पीजी इंक्रीमेंट सब पर लागू करना। सवाल है कि चिकित्सकों का यह आंदोलन जायज है। चिकित्सकों का कहना है कि यह जायज है। वेतन आयोग के बाद पैदा की गई विसंगतियों के हल के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने डॉक्टरों को पंजाब के समकक्ष वेतन देने की घोषणा विधानसभा में की पर ऐसा नहीं किया गया। पहले से वेतनमान तो कुछ ठीक किए गए पर विसंगतियां छोड़ दी गईं।

अगस्त 2009 में विसंगतियों को और बढ़ा दिया गया। जब सरकार ने 2006 और 2008 के बाद नौकरी में आने वाले डॉक्टरों का वेतनमान स्टॉफ नर्स के बराबर कर दिया। इससे डॉक्टरों में असंतोष की भावना और बढ़ गई। इसका नतीजा ये हुआ कि 600 डॉक्टरों की भर्ती के बावजूद 100 से भी अधिक डॉक्टर नौकरी में टिके रहे, वहीं अभी हाल में ही गुडगांव में खुले मेडिसिटी अस्पताल में हरियाणा से दुगना वेतन देने की घोषणा की पेशकश की गई। हरियाणा की आबादी के अनुसार पहले ही अस्पतालों, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टॉफ की भारी कमी है। इससे प्राइवेट चिकित्सा का व्यापार फल-फूल रहा है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों की साख जो थोड़ी-बहुत बंधी हुई है वह भी समाप्त हो जाएगी। एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा देने जैसी सामाजिक जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया है और सभी को प्राइवेट चिकित्सा प्राप्त करने के मजबूर किया जा रहा है। प्राइवेट चिकित्सा सुविधा पाना सबके बस का नहीं है। प्राइवेट चिकित्सा सुविधाओं का सबसे बड़ा विरोधाभाष यह है कि जिन्हें चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है उनकी जेब में पैसा नहीं है। जहां हरियाणा में यह दावा किया जाता है कि हरियाणा पूरे भारत में प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर है। वह सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हरियाणा का स्थान बहुत पीछे है। ऐसे में डॉक्टरों का यह आंदोलन इन स्वास्थ्य सेवाओं को और भी प्रभावित करेगा तथा गरीबों को मिलने वाली छोटी-मोटी स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा जाएगी। यदि सरकार में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो चिकित्सकों के मांगों को नौकरशाही के नजरिए से न देखकर सामाजिक तथा मानवी पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। हरियाणा में एक नौकरशाह का एंट्रीलेवल पर जो स्केल तय किया गया है। वही स्केल डॉक्टरों को मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ हरियाणा को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के बारे में कैसे नंबर 1 बनाया जा सके, इस पर विचार होना चाहिए। हरियाणा सरकार अपने बजट का तीन प्रतिशत से कम हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करती है जबकि वायदा किया हुआ है कि दस प्रतिशत करेगी। राज्य सरकार अपने किए गए वायदे का पालन करती है तो स्वास्थ्य सेवाओं का बजट 1000 करोड़ से बढ़कर 3200 करोड़ हो जाएगा जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले सभी की मांगों को पूरा किया जा सकता है तथा आम लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त की जा सकती है।

अरुंधती राय द्वारा माओवादियों का समर्थन

प्रसिद्ध लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधती राय ने यह कह कर सरकार को एक चुनौती दे दी है कि वे माओवादियों का समर्थन करती रहेंगी, भले ही इसके लिए उन्हें जेल भी क्यों न जाना पड़े। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि माओवादियों का समर्थन करने वालों को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। अरुंधती राय ने माओवादियों की गतिविधियों और उनके अभियान पर एक लेख प्रकाशित करवाया था। इस लेख में उन्होंने यह बताया था कि किस तरह खनिजों की लूट के लिए आदिवासियों को जंगलों से बेदखल किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी बताया था कि किस तरह आदिवासियों का शोषण किया जाता रहा है और माओवादी उनकी रक्षा के लिए संघर्षरत हैं। उन्होंने माओवादियों द्वारा की जा रही हिंसा को जायज ठहराया था और अभी भी ऐसा कर रही हैं। इस पर बुद्धिजीवियों में हलचल मच गई है, क्योंकि बहुत से बुद्धिजीवी माओवादियों के उद्देश्यों के प्रति समर्थन रखते हुए भी उनके द्वारा की जा रही हिंसा को ग़लत बताते हैं। विशेषकर मिदनापुर में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में निर्दोष लोगों की मौतों के बाद बुद्धिजीवियों का एक हिस्सा माओवादियों द्वारा की जा रही हिंसा का विरोध कर रहा है।

देखा जाये तो माओवादियों से किस तरह से निपटा जाये, इस पर सरकार भी असमंजस में दिखाई पड़ती है। केंद्रीय गृहमंत्री ने पहले माओवादियों से कड़ाई से निपटने की बात कही थी। यह भी कहा था कि नक्सलियों से निपटने के लिए अर्द्धसैन्य बलों को हेलिकॉप्टर मुहैया कराये जायेंगे। पर अब गृहमंत्री का सुर बदला हुआ लगता है। वे संबंधित राज्यों की सरकारों पर माओवादियों से निपटने की जिम्मेवारी डालना चाहते हैं। वहीं, माओवादियों से वार्ता करके समस्या का समाधान करने की बात भी की जा रही है। पर माओवादी वार्ता के लिए तैयार नहीं हो रहे।

ऐसी भी चर्चा चली थी कि माओवादियों पर काबू पाने के लिए सेना को भी लगाया जा सकता है, पर अब कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं किया जायेगा। दूसरी तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा सांसद माओवादियों के आधार क्षेत्र में विकास करवाने की बात पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि नक्सलवाद कानून और व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, वरन विकास नहीं होने से उत्पन्न समस्या है। लगभग सभी दलों के राजनेता इस बात पर सहमत हैं कि माओवादियों पर तभी काबू पाया जा सकता है जब उनके आधार क्षेत्र में विकास हो।

यहां सवाल यह उठता है कि आज से पहले सरकार और राजनेताओं के दिमाग में पिछड़े आदिवासी इलाकों में विकास की बात क्यों नहीं आई थी। अब वे वहां आधारभूत संरचना का विकास करना चाहते हैं तो उसके पीछे उनकी मंशा आदिवासियों के कल्याण की नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों के तहत उन्हें दुर्गम इलाकों में आधारभूत संरचना का विकास करना अनिवार्य प्रतीत हो रहा है।

अगर आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पाता है तो पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय निगमों को वहां से खनिजों के दोहन में परेशानी होगी। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में विकास पर अब काफी जोर दिया जा रहा है। सवाल है, इस विकास का फल आदिवासियों को क्या मिलेगा? इसका फल उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और उनका विस्थापन जारी रहेगा।

आदिवासियों को अपनी ज़मीन और जंगल छोड़ कर दर-दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस विकास के परिणामस्वरूप उनके संसाधनों की लूट और भी तेज़ हो जायेगी। लेकिन विकास को बाधित नहीं किया जा सकता। समय के साथ पिछड़े इलाकों का विकास होना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। माओवादियों और आदिवासियों के संगठनों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि विकास के नाम पर उनके संसाधनों की लूट की प्रक्रिया कहीं और ज़्यादा सघन न हो जाये।

जहां तक अरुंधती राय द्वारा माओवादियों के समर्थन की बात है तो उनकी आलोचना इस बात के लिए नहीं की जा सकती कि वे हिंसा का समर्थन कर रही हैं। देखा जाये तो राजसत्ता के पास हिंसा के उपकरण कहीं ज़्यादा हैं। राज्य जो हिंसा कर रहा है, उसका विरोध जब नहीं हो रहा तो माओवादियों द्वारा की जाने वाली हिंसा का विरोध क्यों? वैसे इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि माओवादियों को अंधी हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर उनके द्वारा की जाने वाली हिंसा में निर्दोष लोग मारे जायेंगे तो आम जनता के बीच उनकी छवि खराब हो जायेगी। इसलिए माओवादियों को इसका ध्यान रखना होगा कि कहां सुई और कहां तलवार का उपयोग किया जाये।

- प्रतिनिधि

पेज 8 का शेष भाग : **'मार्गदर्शन' ने लगाया आटो चालकों के जख्मों पर मरहम :** इन अस्पतालों ने बैंकों से कर्ज लेकर व अपनी जमा पूंजी ससे सैंकड़ों करोड़ के अस्पताल मुफ़्त जांच के लिये खड़े नहीं किये हैं, बल्कि कुछ न कुछ मुनाफ़ा कमाने के लिये खडे किये हैं। वैसे ध्यान से देखा जाये तो सर्वोदय ने यह सब मुफ़्त में नहीं किया है। इसके लिए जहां एक ओर आटो चालकों के चार-पांच घंटे बर्बाद हो गये, वहीं दूसरी ओर अस्पताल की अच्छी-खासी मशहूरी हो गई। वास्तव में ये काम उन सरकारी अस्पतालों के हैं जो जनता के पैसे से चलते हैं, जिन्हें न किसी बैंक को ब्याज देना है, न कोई मुनाफ़ा कमाना है। लेकिन सरकार को अपनी अय्याशियों से फ़ुर्सत मिले तभी तो ग़रीब लोगों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देगी। इस दौरान आटो चालकों को वर्दी पहनने, शराब पी कर गाड़ी न चलाने, सुरक्षित गाड़ी चलाने व सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बारे में भी समझाया गया। संस्था ने प्रत्येक आटो चालक का एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कराने के लिए किश्त का आधा भाग जो 138 रुपये बनते हैं, अपनी ओर से जमा कराने की घोषणा की है। यदि इस घोषणा पर अमल हो पाया तो वास्तव में ही चालकों के लिये एक अच्छी सौगात होगी।